

महाराष्ट्र में पशु वाहनों को रोके जाने के खिलाफ पुलिस ने जारी किया सर्कुलर

नवाब मलिक और सना मलिक शेख की पहल पर अजीत पवार की दखल, डीजीपी ने राज्यभर में पशु पकड़-धकड़ और व्यापारियों को परेशान करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया

मुंबई: संवाददाता महाराष्ट्र में पशुओं की पकड़-धकड़, परिवहन में रुकावट और व्यापारियों को परेशान करने की घटनाओं के खिलाफ राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने आदेश जारी कर दिया है। डीजीपी ने राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस प्रमुखों को सर्कुलर भेजते हुए निर्देश दिया है कि पशु वाहनों को गैरकानूनी तरीके से रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह सर्कुलर कुर्देशी समाज की शिकायत के बाद जारी किया गया, जिसमें समाज विरोधी तत्वों पर पशु वाहनों को रोकने और व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था।

गौतलब है कि कुर्देशी समाज और अन्य मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात कर यह शिकायत की थी। प्रतिनिधिमंडल



ने मांग की थी कि पशुओं को लाने वाली गाड़ियों को सुरक्षा दी जाए। इस बैठक का नेतृत्व एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक और विधायक सना मलिक शेख ने किया था। ६ अगस्त को मुंबई में हुई इस मुलाकात के बाद अजीत पवार ने तुरंत डीजीपी से बातचीत कर पशु वाहनों और व्यापारियों

को सुरक्षा देने का निर्देश दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में पशु ले जाने वाले वाहनों को पुलिस या कई बार असंबंधित लोग भी बिना वजह रोक देते हैं। कई मौकों पर इन वाहनों को जब्त कर लिया जाता है, पशुओं को छीन लिया जाता है और मालिकों के

साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कुछ कट्टरपंथी तत्व कानून को हाथ में लेकर डर का माहौल बनाते हैं और कारोबार को ठप करने की कोशिश करते हैं। कई व्यापारियों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कर दिए जाते हैं, जिससे व्यापारिक जगत में बेचैनी फैलती है और आर्थिक नुकसान होता है।

अजीत पवार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को तुरंत कार्रवाई करने और अवैध पकड़-धकड़ या उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी ने राज्यभर की पुलिस के लिए सख्त और स्पष्ट सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि पशु वाहनों को केवल कानून के तहत और ठोस आधार पर ही रोकें जायें, किसी भी व्यापारी या चालक को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी कारोबार बिना रुकावट जारी रह सके। साथ ही, किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून हाथ में लेने की अनुमति न दी जाए, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए।

विधायक सना मलिक शेख ने डीजीपी के इस आदेश को कुर्देशी समाज की बड़ी

जीत बताया और कहा कि यह सब अजीत पवार की समय रहते की गई दखल का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर से व्यापारियों को अपने काम में सुविधा मिलेगी और वे बिना डर-भय के अपना कारोबार आगे बढ़ा सकेंगे। यह आदेश न केवल कुर्देशी समाज बल्कि उन सभी व्यापारियों के लिए राहत है जो लंबे समय से भय और अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। अब उम्मीद है कि पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी और गैरजरूरी कार्रवाई पर रोक लगेगी। यह सर्कुलर ऐसे समय में जारी हुआ है जब राज्य में पशु परिवहन से जुड़े विवाद बढ़ रहे थे और व्यापारियों को लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई के सामाजिक सेवाकों के साथ साथ औरंगाबाद के जावेद कुर्देशी और बीड से नबील ज़मा भी शामिल थे।

कबूतरखाना बंदी के समर्थक मराठा एकीकरण समिति के आंदोलकारियों की गिरफ्तारी

जमीर काज़ी, मुंबई - दादर स्थित कबूतरखाना बंद करने के समर्थन में और कानून हाथ में लेकर विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मराठा एकीकरण समिति ने बुधवार को कबूतरखाने के पास आंदोलन किया। हालांकि, पुलिस ने तुरंत उनकी गिरफ्तारी कर आंदोलन को खत्म कर दिया।

सिर्फ कुछ ही मिनट चले इस प्रदर्शन में राज्य सरकार, पुलिस और महानगरपालिका की पक्षपाती नीतियों के खिलाफ तीव्र विरोध जताया गया। मराठा एकीकरण समिति के सदस्य दादर के कबूतरखाने के पास जमा होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें



हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें तितर-बितर किया, इस दौरान आंदोलकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प भी हुई।

मराठी एकीकरण समिति के गोवर्धन देशमुख ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मराठियों के लिए रक्त बहाया है। उन्होंने कहा कि जब जैन समाज ने चाकू-छुरों के साथ

आंदोलन किया था, तब पुलिस कहाँ थी? हमारे साथ खड़े होने वाले मंत्री नहीं हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ एक विशेष समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोई कानून-व्यवस्था हाथ में लेता है तो हम महामोर्चा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मराठों की वजह से हिंदुत्व सुरक्षित रहा है। यह मुद्दा धर्म का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक विशेष समाज धर्म के नाम पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, हथियार दिखाकर और मोर्चे निकालकर असंतोष फैला रहा है। उन्हें समय रहते रोकना चाहिए, अन्यथा हमें भी जवाबी मोर्चे निकालने पड़ेंगे।

आंदोलकारियों ने आरोप लगाया

कि कुछ गिने-चुने लोग और समूह जानबूझकर दादर के कबूतरखाने के बंदिस्त फीडिंग ज़ोन को तोड़कर कबूतरों को खिलाने की अवैध गतिविधि कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि संबंधित सभी व्यक्तियों और आयोजकों पर तुरंत त्रखट दर्ज की जाए और उच्च न्यायालय अवमानना अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा मुंबई महानगरपालिका कानून के तहत सख्त कार्रवाई हो।

आंदोलन के लिए कबूतरखाने के पास जुटे आंदोलनकारियों को, प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान सरकार की पक्षपाती नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई।

यूम-ए-आजादी पर कौन क्या खाएगा, क्या यह सरकार तय करेगी? बीजेपी और देश की आजादी का क्या संबंध?-हर्षवर्धन सपकाळ



मुंबई: यूम-ए-आजादी एक राष्ट्रीय पर्व है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था, तब बीजेपी के पूर्वज कांग्रेस के साथ थे, कुछ लोग अंग्रेजों की पेंशन खाते हुए उनकी मदद कर रहे थे। अपने पूर्वजों पर लगे इन काले धब्बों को छुपाने के लिए ही बीजेपी यह तय करने लगी है कि १५ अगस्त को कौन क्या खाए। यह कड़ा प्रहार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने किया।

तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपकाळ ने कहा कि वन नेशन, वन लीडर का एजेंडा लाकर एक ही नेता, एक ही पहनावा, एक ही भाषा और एक ही खान-पान के जरिए देश की विविध संस्कृति को खत्म करना और तानाशाही लाना बीजेपी का उद्देश्य है। हिंदू-मुस्लिम विवाद तो रोज चलता है, पहले मराठा-ओबीसी विवाद खड़ा किया गया, फिर मराठी-हिंदी विवाद, और अब १५ अगस्त को मांस न खाने का आदेश जारी किया गया है। यह जनता पर हर तरह का सरकारी नियंत्रण लाने की कोशिश है।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कबूतरों को जीने का अधिकार है, लेकिन इंसानों को भी जीने का अधिकार है। कबूतरों के पंख और बीट से फेफड़ों की गंधी बीमारियां होती हैं, जिनसे कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए नागरिकों के स्वास्थ्य का सवाल भी उतना ही अहम है। लेकिन बीजेपी सरकार ने जानबूझकर कबूतर जिहाद शुरू किया

है। सरकार ने अडानी को आधी मुंबई सौंप दी है और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के पास भी मुंबई में काफी जमीन है। इस जमीन पर लोढ़ा और अडानी विशेष कबूतर प्लाज़ा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में गैंगवार जारी है, भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस सरकार ने राज्य को दिवालिया होने की कगार पर ला दिया है और वोट चोरी की हकीकत से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही कबूतरखानों का मुद्दा हवा दी जा रही है। सपकाळ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने कार्यकाल में राज्य में दंगा नियंत्रण बल बनाया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने दंगा करो बल बनाया है, जिसे नागपुर, पुणे, नासिक और मुंबई में भेजकर सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसा जमाने के महान नेता महावीर ने विनम्रता, बुद्धिमत्ता और नम्रता की शिक्षा दी थी, लेकिन उस पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ की मौजूदगी में एनएसयूआई के नवनियुचित महाराष्ट्र अध्यक्ष सागर सालुखे का शपथ ग्रहण कार्यक्रम तिलक भवन में हुआ। पूर्व अध्यक्ष आमिर शेख ने पदभार सालुखे को सौंपा। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव बीएम संदीप, पूर्व मंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, पूर्व अध्यक्ष आमिर शेख, एआईसीसी के रिसर्च डिपार्टमेंट की लेनी जाधव, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले समेत सैकड़ों छात्र उपस्थित थे।

आयोग की एकतरफा भूमिका घातक-सांसद पाटील



केज, १३ - राज्यसभा की सांसद व कांग्रेस नेता रजनी पाटील ने कल इंडिया गठबंधन के आंदोलन में आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की एकतरफा भूमिका लोकतंत्र के लिए घातक है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीड की सांसद रजनी पाटील इस आंदोलन में शामिल हुईं। सरकार ने पुलिस दमन के जरिए इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन सांसद रजनीताई पाटील ने, महिला सांसद होने के बावजूद, इस विरोध से पीछे न हटते हुए, रास्ता रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया।

हालांकि, मिलने के लिए जाते समय इंडिया गठबंधन के सांसदों को पुलिस ने रोक दिया और हिरासत में भी लिया। फिर भी वह पीछे नहीं हटीं। वोट चोरी के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। मतगणना में पारदर्शिता और मतदाता सूची में हेरफेर रोकने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया। इस दौरान सांसद रजनी पाटील आक्रामक नज़र आईं।

शहर के विभिन्न विषयों पर विधायक संदीप क्षीरसागर ने नगर परिषद में लिया आढावा

महत्वपूर्ण विषयों को तुरंत निपटाने के लिए निर्देश

बीड, १३ (प्रतिनिधि) - बीड शहर के नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधायक संदीप क्षीरसागर ने बुधवार (१३ तारीख) को आढावा बैठक आयोजित की। इस बैठक में शहर के नागरी (शहरी) प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हुए, आवश्यक और महत्वपूर्ण विषयों को तत्काल हल करने के निर्देश विधायक क्षीरसागर ने मुख्याधिकारी और नगर परिषद प्रशासन को दिए।

बीड शहर के कई शहरी मुद्दे लम्बे समय से लंबित हैं। इस संदर्भ में विधायक संदीप क्षीरसागर लगातार शासन और प्रशासन स्तर पर प्रयासरत हैं। इसी क्रम में बीड नगर परिषद के स्तर पर विभिन्न लंबित विषयों की समीक्षा के लिए, बीड नगर परिषद के नवनियुक्त मुख्याधिकारी शैलेश फडसे तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विधायक क्षीरसागर ने विस्तृत चर्चा व आढावा लिया। साथ ही, शहर के नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रशासनिक स्तर से तुरंत सुलझाने के निर्देश भी दिए।

इस बैठक में पूर्व विधायक सय्यद सलीम, नगर परिषद के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख रूप से निम्न विषयों पर चर्चा हुई-

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा की ऊँचाई बढ़ाना और सौंदर्यीकरण



चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। शहर की स्वच्छता और जल आपूर्ति व्यवस्था पर आढावा। शहर में पार्किंग व्यवस्था हेतु प्रस्तावित ३७(ए) प्रस्ताव पर निर्णय। घरकुल योजना, विद्युत आपूर्ति तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण पर चर्चा।

पेट बीड क्षेत्र के मछली बाजार भवन, पुरानी सब्जी मंडी के मटन मार्केट भवन तथा सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स स्थित सब्जी मंडी भवन की स्थिति पर समीक्षा।

उर्दू घर निर्माण के लिए भूमि निर्धारित करना। कोडवाड़ा (पशु पकड़ने का केंद्र) के

नवीनीकरण पर चर्चा। डब्लूड प्लांट से जुड़े कार्यों की समीक्षा।

आवारा पशुओं के लिए नया कोडवाड़ा बनाना।

शहर के प्रमुख मार्गों को जिला नियोजन समिति के पास प्रस्तावित करने पर चर्चा - जिसमें धानोरा रोड, धानोरा रोड से अंकुश नगर रोड, नवीनीकरण पर चर्चा।

स्टेडियम क्षेत्र का रोड, बुंदेलपुरा रोड, कवाड़ गली रोड समेत अन्य महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों का कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना पर भी चर्चा हुई।

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित बस्ती योजना के तहत कई विकास कार्यों को मंजूरी देने पर विचार-विमर्श।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

नवनियुक्त सीओ को बीड़ शहर बचाव मंच ने शहर की समस्याओं से कराया अवगत

SDPI पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक में प्रमुख उपस्थिति, शहर की समस्याएं रखी गईं

बीड़ प्रतिनिधि – नगर परिषद के नव-नियुक्त मुख्याधिकारी शैलेश फड्से से बीड़ शहर बचाव मंच के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर शहर की सड़कों, पानी, स्वच्छता, बिजली, आवारा जानवर, हाईवे पर यू-टर्न, यातायात, नो पार्किंग जैसी सभी समस्याएं विस्तार से रखीं। विस्तृत चर्चा के बाद सीओ ने सड़कों के काम को छोड़कर बाकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता व तुरंत करने का आश्वासन दिया।

शहरवासियों की ओर से सीओ का स्वागत बचाव मंच, विभिन्न संगठनों, डड्डाख पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया और ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष नितीन जायभाये, प्राचार्य डी.जी. तांदळे, आबेद भाई सैयद, एडवोकेट नितीन वाघमारे, अशोकराव येडे, लताताई राऊत, साहस औदाडे, निदेश

उपाध्ये, सुधीर भाई देशमुख, सादेक भाई सैयद सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मार्गदर्शक मौजूद थे।

बैठक में मुख्य रूप से निम्न मांगें रखी गईं –

शहर के सभी हिस्सों की सड़कों के गड्ढे तुरंत भरे जाएं।

लौटते मौनसून से पहले पूरे शहर में जगह-जगह जमा कचरे के ढेर हटाए जाएं और नालों की सफाई अभियान चलाकर जाम नालों को तुरंत खोला जाए, ताकि बारिश में किसी अनहोनी और नागरिकों की परेशानी से बचा जा सके।

शहर, खासकर विस्तारित क्षेत्रों में, स्ट्रीट लाइट्स की भारी कमी है। रात में अंधेरे के कारण महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों को शरारती तत्वों, कुत्तों और आवारा पशुओं से दिक्रत होती है। अतः सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाए और तत्काल लगाई जाएं।

बीड़ शहर बचाव मंच ने सर्वे कर स्ट्रीट लाइट्स की आवश्यकता के अनुसार सूची नगर परिषद के विद्युत विभाग को सौंपी है।

बीड़ शहर में पानी की आपूर्ति हर पांच दिन पर नियमित की जाए।

नगर परिषद के राजस्व कर वसूली विभाग से नागरिकों को हो रही परेशानियां दूर की जाएं, वसूली प्रक्रिया में सुधार हो और नागरिकों की सुविधा के अनुसार कर वसूली की जाए।

बंद पड़े घंटा गाड़ियों और कचरा उठाने वाले ट्रैक्टरों को तत्काल शुरू किया जाए। आवारा कुत्तों और पशुओं के कारण शहर में हादसे और ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, इसलिए इनका तुरंत बंदोबस्त किया जाए।

नगर रोड पर सड़क डिवाइडरों में यू-टर्न बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

शहर में टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा छिड़काव जैसी कार्रवाई तुरंत हो।

पांगरी रोड क्षेत्र में सौभाग्य लॉन्स से आगे मुख्य सड़क और आसपास की बस्तियों में स्ट्रीट लाइट नहीं हैं, यहां तत्काल लाइट लगाई जाए। नगर परिषद हद के भीतर यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी सड़कों – नगर रोड व डी.पी रोड को जोड़ने वाली तहसील-सामाजिक न्याय भवन के बीच की सड़क,

सुभाष रोड मंडी चौक से स्टेडियम होते हुए जालना रोड तक पत्रकार रोड,

डी.पी रोड से आदर्श नगर होते हुए उमाकिरण, शाहूनगर, पांगरी रोड जोड़ने वाली सड़क, पांगरी रोड से गिराम नगर क्षेत्र की मुख्य जोड़ सड़क,

तथा कॉलोनिनों की आंतरिक सड़कों – को तत्काल मजबूत सीमेंट सड़कों में बदला जाए। शिक्षा कर जैसे अव्यवहारिक और नागरिकों से असंबंधित कर तुरंत रद्द किए जाएं।

निर्लांबित १८ अनुकंपा आधार पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों को नगर विकास के माध्यम से बहाल किया जाए और ३२ महीने का बकाया वेतन दिलाया जाए।

अमृत जल योजना और भूमिगत नाली योजना लागू की जाए और वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जाए।

पुरानी अनुपयोगी पानी की टंकियां बंद कर नई टंकियां का उपयोग शुरू किया जाए।

कालिकादेवी महाविद्यालय में विश्व स्तनपान सप्ताह संपन्न

शाहू, फुले, आंबेडकर, कलाम के विचारों के आचरण में सफलता-दादासाहेब मुंडे

शिरूर कासार (प्रतिनिधि) – आरोग्य सेवा केंद्र, कालिकादेवी महाविद्यालय के बती से जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय, कानोबाची वाड़ी में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और ग्रामीणों को स्तनपान का महत्व बताया गया।

कार्यक्रम में बोलते हुए प्रो. अफरोज़ सैयद ने कहा कि स्तनपान का संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन करना समय की आवश्यकता है, क्योंकि स्तनपान से बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। हर वर्ष १ अगस्त से ७ अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह एक वैश्विक अभियान के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान माताओं और शिशुओं को कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य डॉ. विश्वास कंधारे ने कहा कि आज की किशोरी, कल की माता होती है, इसलिए सशक्त और स्वस्थ किशोरी का सशक्त माता बनना महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से महाविद्यालय और आरोग्य सेवा केंद्र कार्यक्रम है। कार्यक्रम का संचालन प्रो. रमेश लांडगे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्राथमिक शिक्षक तांबे सर ने किया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थी-विद्यार्थिनियाँ, आंगनवाड़ी सेविका सुजाता जाधव, महिला ग्रामवासी और शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हिए पंपलेट्स का वितरण किया।

कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य डॉ. विश्वास कंधारे ने कहा कि आज की किशोरी, कल की माता होती है, इसलिए सशक्त और स्वस्थ किशोरी का सशक्त माता बनना महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से महाविद्यालय और आरोग्य सेवा केंद्र कार्यक्रम है। कार्यक्रम का संचालन प्रो. रमेश लांडगे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्राथमिक शिक्षक तांबे सर ने किया। इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थी-विद्यार्थिनियाँ, आंगनवाड़ी सेविका सुजाता जाधव, महिला ग्रामवासी और शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बीड़, दिनांक १३/८/२०२५

अल्पसंख्यक पुलिस सिपाही भर्ती पूर्व प्रशिक्षण सत्र २०२५-२६, शासन की योजना अंतर्गत आज़ाद हिंद संस्था, बीड़ द्वारा ५० उम्मीदवारों के लिए शुरू किया गया है। लिखित और ग्राउंड की पहली प्रैक्टिस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के सत्कार कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्य महासचिव दादासाहेब मुंडे ने कहा कि शाहू, फुले, आंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचारों का आचरण करें, उसी में सफलता है। उन्होंने कहा, अगर आप केवल एक

अंक कम लाते हैं, तो माता-पिता और समाज आपकी सराहना करेगा, लेकिन यह भी सोचेगा कि एक अंक क्यों कम आया। आज माता-पिता की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। इसलिए आपको किताबों के ज्ञान के साथ शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा, तभी सफलता का असली मूल्य होगा।

थ्योरी और ग्राउंड दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छह बच्चों का सत्कार माननीय दादासाहेब मुंडे, नवनियुक्त उपशिक्षणाधिकारी बीड़ माननीय जमीर शेख, मजलगांव की माननीय शिक्षा विस्तार अधिकारी श्रीमती मुनावर सुल्ताना, राज्य अध्यक्ष अनिल जाधवर, और वक्फ अधिकारी औरगबाद शोएब शेख के हाथों किया गया।

इस अवसर पर जमीर शेख ने कहा कि वे बच्चों को कक्षा में समय देकर उन्हें सफलता तक पहुंचाने में मदद करेंगे, लेकिन बच्चों को संस्था और शिक्षकों के संरक्षण से दूर नहीं होना चाहिए। मुनावर सुल्ताना ने कहा कि आप प्रयास करते रहें, पुलिस बनकर अपने माता-पिता और संस्था का नाम रोशन करें और हमें फिर से आपके सत्कार का अवसर दें। कार्यक्रम में माननीय दादासाहेब मुंडे, जमीर शेख, मुनावर सुल्ताना, अनिल जाधवर का संस्था की ओर से सत्कार किया गया और आगे की यात्रा के लिए शेख मुसा ने शुभकामनाएं दीं। मार्गदर्शन से बच्चे प्रसन्न और उत्साहित दिखाई दे रहे थे।

बालेपीर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की माँग, खमरोद्दिन ने अजित दादा से की अपील

रविवार को निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार और मज़दूरों की बैठक, रेत नीति तय करने की माँग

बीड़ संवाददाता

कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के शहराध्यक्ष मोहम्मद खमरोद्दिन ने बीड़ शहर के बालेपीर क्षेत्र में नागरिकों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की माँग उपमुख्यमंत्री अजित पवार से की है। यह माँग उन्होंने अजित दादा के बीड़ शासकीय विश्रामगुह आगमन के दौरान ज्ञापन देकर रखी।

खमरोद्दिन ने अपने निवेदन में कहा कि बीड़ शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन बालेपीर इलाके में सुसज्ज अस्पताल की कमी के कारण लोगों को इलाज के लिए ज़िला अस्पताल जाना पड़ता है। इस तळेगांव, काकडहिरा और पिपरगव्हाण जैसे क्षेत्रों में लगभग ५० हजार निवासी रहते हैं। यहाँ प्राथमिक और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है।

नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले बालेपीर, गोंरे वस्ती, बांगर नाला, राजू नगर, पंढरी नगर, धानोरा रोड, अंकुश नगर, जायकवाड़ी वसाहत, भक्ती कंस्ट्रक्शन, ग्रामसेवक कॉलोनी, लिपरागव्हाण रोड, रोशनपुरा, नई ईदगाह, कालिका नगर, गवळवाड़ी, तळेगांव, काकडहिरा और पिपरगव्हाण जैसे क्षेत्रों में लगभग ५० हजार निवासी रहते हैं। यहाँ प्राथमिक और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है।

खासकर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और रात के समय एम्बुलेंस न मिलने से जान का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए बालेपीर क्षेत्र में सुसज्ज और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। खमरोद्दिन ने माँग की कि बालेपीर में कम से कम ५० बिस्तरों वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया जाए, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक, नर्स, दवा वितरण केंद्र और प्राथमिक जांच सुविधा उपलब्ध हो। इस अस्पताल के लिए आवश्यक भूमि तुरंत अधिग्रहित कर उपलब्ध कराई जाए। इस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि यह विषय नीतिगत है और वे इस मामले में सरकार को सिफारिश करेंगे।

बीड़ प्रतिनिधि

बीड़ ज़िले में पंजीकृत आरसीसी निर्माण मज़दूर संगठन की ओर से बीड़ शहर के अमन लॉन्स में रविवार, १७ अगस्त २०२५ को सुबह १०:३० बजे बैठक आयोजित की गई है। पिछले दो वर्षों से ज़िले में रेत बंद होने के कारण मज़दूरों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ सरकारी कार्यों को छोड़ दें तो लगभग सभी निजी निर्माण कार्य ठप पड़े हैं।

संगठन के ज़िलाध्यक्ष अलीम पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने

और मज़दूरों की भूखमरी रोकने के लिए ज़िलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला जाएगा तथा सरकार से रेत नीति तय करने की माँग की जाएगी।

पत्र में आगे कहा गया है कि पिछले दो वर्षों से ज़िले में रेत पूरी तरह बंद है, जिसका सीधा असर निर्माण मज़दूरों पर पड़ा है। आरसीसी, फ़र्शी, रंग-रोगन, प्लंबिंग, वायरमैन, पीओपी, खोदाई, लिफ्ट मशीन ऑपरेटर जैसे मज़दूर और ठेकेदार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। साथ ही सीमेंट, ईट, गिट्टी, रंग, फ़र्शी विक्रेता और हाथवा चालक-मालिक भी प्रभावित हुए हैं।

इस बंदी के कारण राज्य सरकार की आमदनी में भी भारी गिरावट आई है। बीड़ ज़िले में गन्ना काटने वाले मज़दूरों के बाद सबसे बड़ी संख्या निर्माण मज़दूरों की है। कई गन्ना मज़दूर सीजन के बाद निर्माण कार्य में लगते हैं, लेकिन रेत बंदी के कारण यह रोज़गार भी ठप हो गया है। मोर्चे के लिए सभी ठेकेदार, मज़दूर, रंग-रोगन दुकानदार, हार्डवेयर व्यापारी, प्लंबिंग सामान विक्रेता, सीमेंट विक्रेता, वेल्टिंग वर्कशॉप संचालक, ईट भट्टा संचालक, हाथवा चालक और मालिकों को रविवार को समय पर बैठक में पहुँचने का आह्वान किया गया है। बैठक में मोर्चे की रणनीति तय की जाएगी और सरकार को मज़दूरों की समस्याओं पर ज्ञापन दिया जाएगा।

हिरापुर के बाजार में कोई मवेशी नहीं खरीद रहा, किसानों के सामने गहरा आर्थिक संकट!

काजी अमान / गेवराई – बिना किसी कानूनी अधिकार के स्वयंभू गोरक्षक, महाराष्ट्र राज्य में गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून की आड़ में कुश्नी समाज के व्यापारियों को परेशान कर उनकी आर्थिक लूट कर रहे हैं। इस कारण, कुश्नी बिरादरी ने पूरे राज्य में मवेशियों की खरीद-बिक्री का लेन-देन बंद करने का कठोर निर्णय लिया है, जिसके चलते पशुपालक किसानों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गेवराई तहसील के हिरापुर में हर मंगलवार लाने वाले मवेशी बाजार में अब कोई भी मवेशी खरीदने नहीं आ रहा, जिससे किसानों को अपना पशुधन वापस लेकर लौटना पड़ रहा है। बाहर से आने वाले व्यापारी भी मवेशी बिक्री लाना बंद कर चुके हैं।

इससे कर वसूली के जरिए होने वाली आय पर गंभीर असर पड़ा है, और हिरापुर ग्राम पंचायत को हर सप्ताह ५० हजार रुपये का घाटा सहना पड़ रहा है। अब तक लगभग ढाई लाख रुपये का नुकसान होने की बात सामने आई है।

गेवराई तहसील के हिरापुर में लगने वाला यह सामाहिक मवेशी बाजार न केवल ज़िले में, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यहां गेवराई, बीड़, पात्रुड, मजलगांव, परली, पाथर्डी, बोधेगांव, घोडगांव (ता. शेवागांव), पाचोड़, जामखेड (अहमदनगर), छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), परभणी, लेह कंधार (मालेगांव), धिर्वंडी (मुंबई) समेत मराठवाड़ा और राज्य के कोने-कोने से व्यापारी बैल, भैंस, वगार आदि प्रकार के मवेशी बिक्री के लिए लाते थे।

लेकिन महाराष्ट्र में गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून लागू होने के बाद मवेशी ले जाने वाले व्यापारियों के वाहन, तथाकथित गोरक्षक और स्वयंघोषित संगठनों के पदाधिकारी, बिना किसी

ग्रामपंचायत को हर सप्ताह ५० हजार का नुकसान

व्यापारियों में भय का माहौल है, जिसके कारण राज्य के कुश्नी समाज के व्यापारियों ने मवेशियों की खरीद-बिक्री के लेन-देन में हिस्सा न लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। इस कठोर निर्णय के चलते हिरापुर का मवेशी बाजार ठप हो गया है।

किसान, अपने सुख-दुःख में ज़रूरत पूरी करने के लिए पशुधन बेचते हैं। लेकिन कुश्नी बिरादरी के इस निर्णय से पशुपालकों पर भारी संकट आ गया है और उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। मां खिलाए नहीं और बाप भीख मांगने न दे जैसी स्थिति में किसान फंस गए हैं।

वर्तमान में खेती का खर्च किसानों को भारी पड़ रहा है, इसलिए सरकार पशुपालन को एक सहायक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देती है और इसके लिए अनुदान भी देती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून

ने किसानों और व्यापारियों दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। साथ ही, वन्यजीव संरक्षण कानून के कारण किसानों की फसलों को वन्य जीव नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस तरह, किसान दोहरी मार झेल रहा है।

हिरापुर के इस सामाहिक बाजार में हर मंगलवार ५०० से ६०० मवेशियों की बिक्री होती थी, जिससे ग्राम पंचायत को कर वसूली के माध्यम से हर सप्ताह लगभग ६० हजार रुपये की आय होती थी। लेकिन कुश्नी समाज के व्यापारियों द्वारा मवेशी खरीद बंद करने के फैसले से यह आय घटकर केवल १० हजार रुपये रह गई है। वहीं, मवेशी खरीदार न होने से, अपनी ज़रूरतें पूरी न कर पाने के कारण किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।